

an>

Title: Regarding houses constructed in Red Zone under Ministry of Defence.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूणे के करीब पिंपरी चिंचवड मावल में रक्षा विभाग के अंतर्गत रेड जोन एरिया में पक्के घरों में रह रहे लोगों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, पिछले अनेक वर्षों से पिंपरी, चिंचवड, मावल में लगभग एक लाख मकान बने हैं, जिसमें करीब चार से पांच लाख लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं, जिसमें राज्य सरकार, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि अनेक संस्थाओं ने डेवलपमेंट प्लान मंजूर किया है। उसके अंतर्गत अधिकृत परमिशन ले कर मकान लीगली बनाए गए हैं। इसी एरिया में कई हजार मकानों को बिजली, पानी एवं रास्तों की सुविधा दी गई है। सभी मकानों का लीगली प्रॉपर्टी टैक्स आज भी करोंडों में वसूल किया जाता है, लेकिन वर्ष 2013 में पूना कलेक्टर ने इस क्षेत्र को रेड जोन के अन्तर्गत घोषित किया है। शुरु में रेड जोन का क्षेत्र छह सौ यार्ड था, बाद में उसे बढ़ाकर दो हजार यार्ड तक किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस एरिया में जो रेड जोन बना है, जो मकान इसके अन्तर्गत आते हैं, रक्षा मंत्री जी, रक्षा सचिव इसके ऊपर ध्यान दें और इन मकानों को अधिकृत किया जाये।